Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा -12

अध्याय - 6

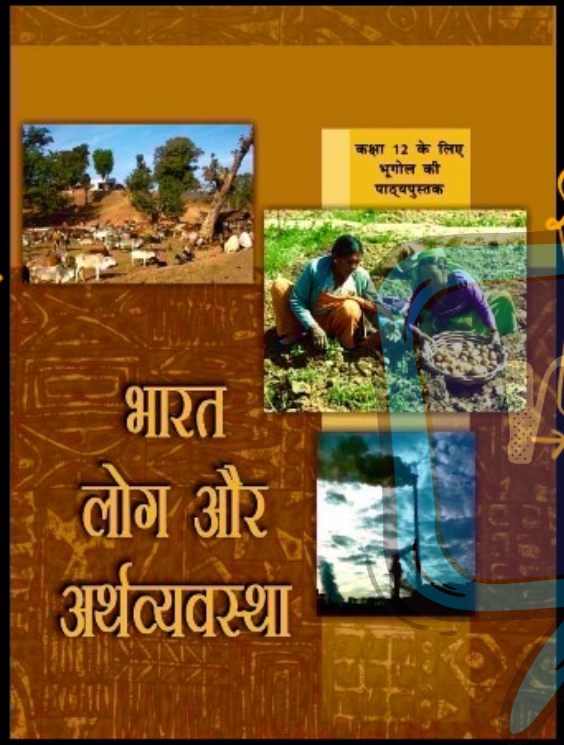
भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास

भाग - 2

पंकज वैष्णव

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



विषय-सूची

	आमुख	iii
	पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	v
	इकाई I	
1.	जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन	1-14
	इकाई II	
2.	मानव बस्तियाँ	15-20
	इकाई III	
3.	भूसंसाधन एवं कृषि	21-40
4.	जल-संसाधन	41-52
5.	खनिज तथा ऊर्जा संसाधन	53-64
6.	भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास	65-73
	इकाई IV	
7.	परिवहन तथा संचार	74-83
8.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	84-92
	इकाई V	
9.	भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ	93-103
	परिशिष्ट	104-111
	शब्दावली	112
	संदर्भ पुस्तकें	113-114

© NCERT not to be republished

C-2 : प्रवास - प्रकार, कारण, परिणाम ×

C-3 : मानव विकास ×

C-4 : निर्माण उद्योग ×

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q :- योजना आयोग का गठन कब हुआ था?

(a) 1947

(b) 1950

(c) 1991

(d) 2015



1947 → 1950.

पंचवर्षीय योजना

1 — 12

2012-2017

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q:- नीति आयोग का गठन हुआ था :-

(a) 15 अगस्त 1947

(b) 26 जनवरी 1950

(c) 2 अक्टूबर 1991

(d) 1 जनवरी 2015

NITI

NITI Aayog — National Institution for Transforming India — सत्यमेव जयते

योजना आयोग - 1950

12 → 2012-2017

नीति आयोग 2015

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

प्र:- प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है :-

(a) 1951-56

(b) 1961-66

(c) 1971-76

(d) 1981-86

योजना आयोग - 1950

1 — 1951-56 (कृषि)

12 — 2012-2017

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q:- भरमौर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?

(a) पंजाब

(b) झारखंड

→ (c) उत्तराखंड

(d) हिमाचल-प्रदेश



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



1. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

देश में 17% भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र है तथा यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है।

ऐसे क्षेत्र दो प्रकार के हैं :-

(अ) वे जो सम्पूर्ण राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे- पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख

(ब) वे जो किसी राज्य के भाग हैं। जैसे- असम के कार्बी आंगलौंग एवं उत्तरी कछार जिले, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला

इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एवं केरल में पाया जाता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



- ✓ नियोजन
- ✓ सतत् पोषणीय विकास
  - पर्यावरण ✓
  - आने वाली पीढ़ी ✓

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊँचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप-योजना लागू नहीं है।
- उक्त समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए निम्न सुझाव दिये-

1. सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं;
2. स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास;
3. जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश-उन्मुखी बनाना;

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

4. अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो;
5. पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुँचाना;
6. पारिस्थिकीय संतुलन बनाए रखना।

पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएँ मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है यही कारण है कि इनकी स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र हेतु अलग विकास योजनाओं को बनाने की आवश्यकता है

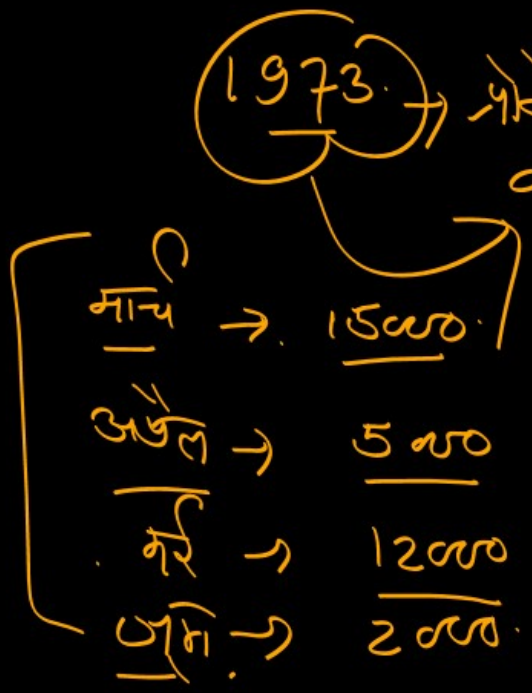
Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी, मृदा संरक्षण एवं ग्रामीण उद्योग पर बल दिया गया है।
- पर्वतीय क्षेत्र, (विशेषकर हिमालय क्षेत्र) जैव-विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ औषधीय पौधे, फलों, फूलों एवं वन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ पायी जाती है। अतएवं यहाँ की मूल्यवान पादप एवं प्राणि संपदा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु जैव आरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और जीनकेन्द्रों को स्थापित करने की जरूरत है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



2. सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP)

- इसकी शुरूआत सन् 1973 में की गयी थी
- इसका उद्देश्य भूमि, जल एवं पशु संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, पारिस्थितिक संतुलन का पुनर्स्थापन और लोगों (विशेषकर कमजोर वर्गों) की आय का स्थिरीकरण करना है।
- 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया। प्रारंभ में केवल सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया था परन्तु उसके बाद में अनेक कार्यक्रम भी जोड़े गये जो निम्न है।

1. जल संसाधनों का विकास एव प्रबन्धन।
2. मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण उपाय।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



3. सामाजिक तथा कृषि वानिकी पर विशेष बल सहित वृक्षारोपण।
4. भेड़ पालन सहित चरागाह विकास एवं प्रबंधन।
5. पशुपालन एवं डेयरी विकास

भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि आदि है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

mg missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



केस स्टडी

भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम

क्षेत्र – हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर व होली तहसील

जनजाती – गद्दी जनजाती का निवास स्थान

भाषा – गद्दीयाली

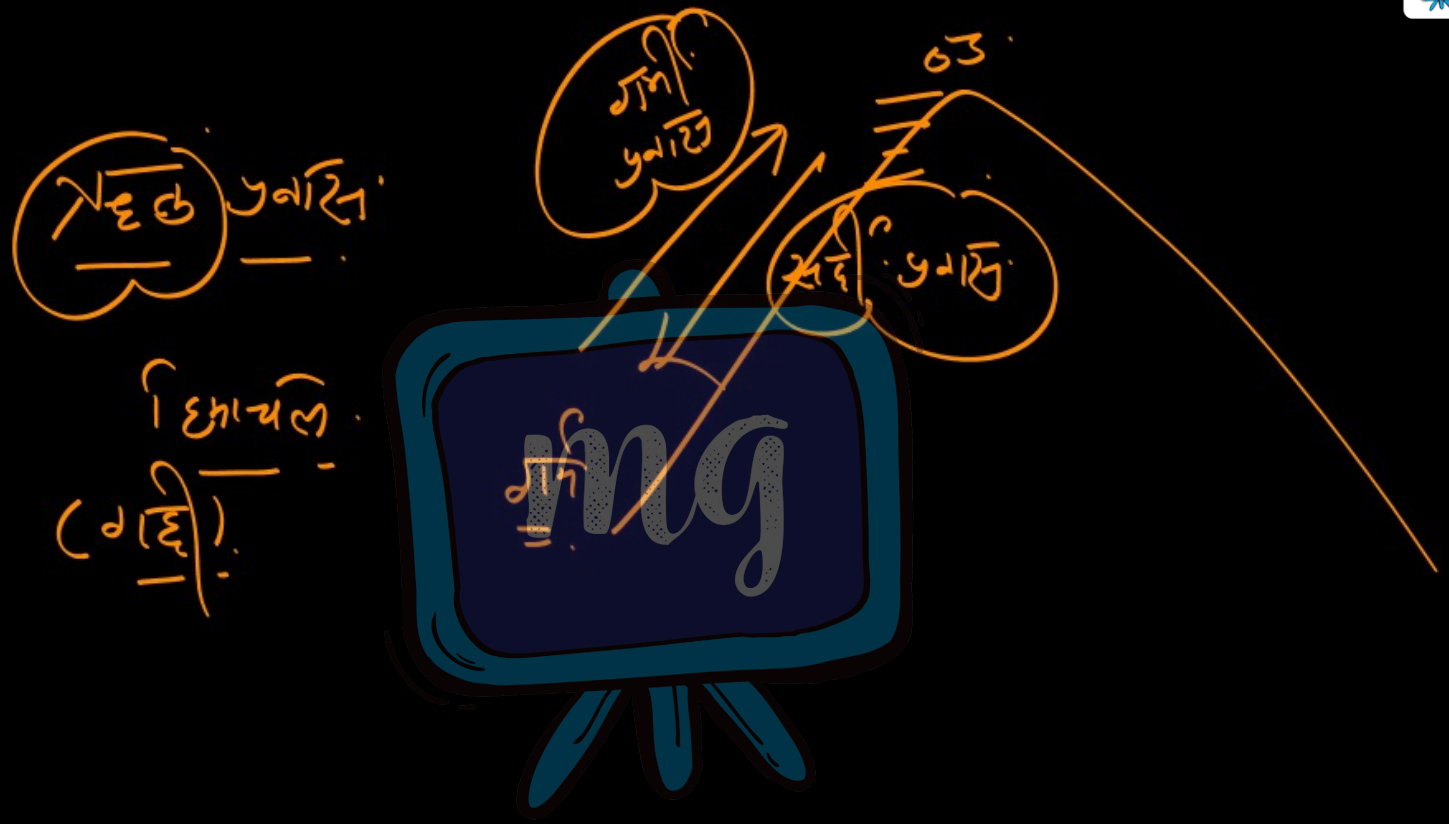
विशेषता – हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करते हैं।

जलवायु – कठोर जलवायु है।

संसाधन – आधारभूत संसाधन कम है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



- सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित है।
- इनका आर्थिक-आधार मुख्यरूप से कृषि और इससे संबद्ध क्रियाएँ जैसे- भेड़ व बकरी पालन है।
- 1970 में गद्दी अनुसूचित जनजातियों में शामिल की गयी।
- 1974 में जनजातीय उप-योजना प्रारंभ हुई।
- उक्त योजना से परिवहन एवं संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता दी गयी।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

अब इस उपयोजना से विद्यालय, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास भी हो रहे हैं।

इस उपयोजना के लागू होने से सामाजिक लाभ

- साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि
- लिंगानुपात में सुधार
- बाल-विवाह में कमी
- स्त्री साक्षरता 1.88% (1971) से बढ़कर 65% (2011) हो गयी
- साक्षरता में लिंग असमानता कम हुई

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

जीवन-निर्वाह कृषि व पशुचारण से बदलकर दाल व अन्य नगदी फसलों की खेती में बढ़ोत्तरी हुई।



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

सतत पोषणीय विकास

'विकास' शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किये गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है।

वृद्धि और विकास

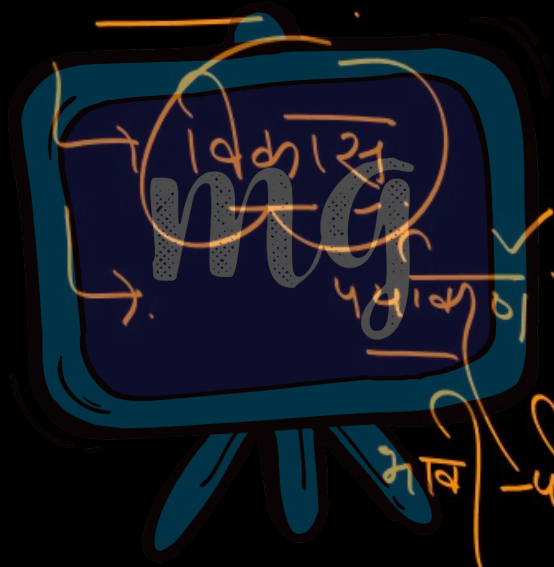
वृद्धि – वर्तमान स्थिति से सकारात्मक मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं।

विकास – वर्तमान स्थिति से सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

सतत् पोषणीय विकास (Sustainable Development)



भावी पीढ़ियों की जरूरत

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

1939 - 1945 (द्वितीय विश्व युद्ध)

1947

1983 → 1987 → रिपोर्ट "हमारा साझा भविष्य"

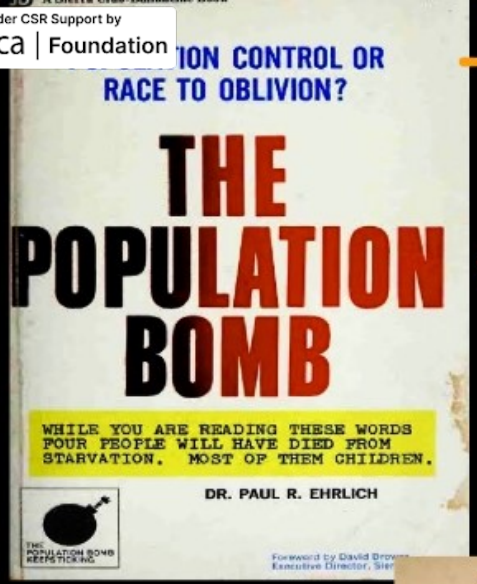
सतत पोषणीय विकास की अवधारणा

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 60 के दशक के आरंभ तक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भौतिक पूँजी में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी।
- जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में मापा गया।
- गरीबी का स्तर बढ़ गया क्योंकि असमान वितरण पाया गया।
- प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

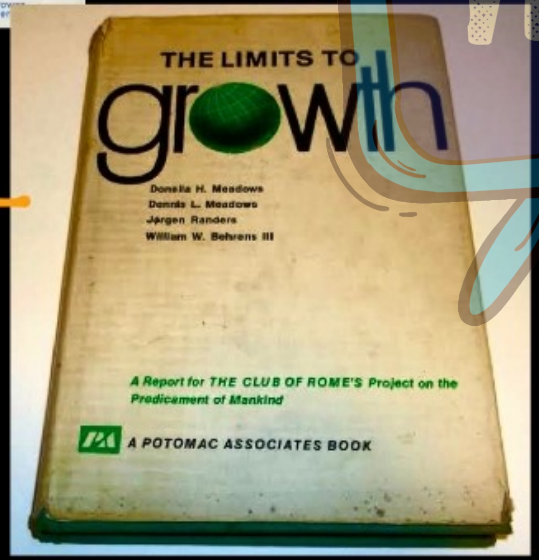
'द पोपुलेशन बम'



1968 → 🍎
1972 → M

1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक 'द पोपुलेशन बम' तथा 1972 में मीडेस की पुस्तक 'द लिमिट टू ग्रोथ' ने इस ओर अपना ध्यान खींचा।

द लिमिट टू ग्रोथ –



1980 के दशक में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का विकास हुआ जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थाना हुई। नार्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड को इसका अध्यक्ष बनाया। इसलिए इसे ब्रंटलैंड आयोग भी कहते हैं।